



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 397]
No. 397]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 1998/आश्विन 24, 1920
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 1998/ASVINA 24, 1920

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1998

सा.का.नि. 621 (अ).—दिनांक 19 दिसम्बर, 1957 के भर्ती तथा सेवा शर्तों आदेश सं. 185 द्वारा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों पर लागू किए गए मूल नियमों के नियम 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सभा के अध्यक्ष लोक सभा सचिवालय (आवासों का आबंटन) नियम, 1974 में और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को लोक सभा सचिवालय (आवासों का आबंटन) द्वितीय संशोधन नियम, 1998 कहा जाएगा।
(2) इन नियमों को 1 जून, 1998 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।
2. लोक सभा सचिवालय (आवासों का आबंटन) नियम, 1974 के नियम 17 में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि आबंटी की मृत्यु हो जाने के मामले में उसका परिवार लाइसेंस शुल्क की सामान्य राशि का भुगतान करके एक और वर्ष के लिए सरकारी आवास अपने अधिकार में रखने का पात्र होगा। सरकारी आवास रखने की अवधि को बढ़ाने की अनुमति उन मामलों में नहीं दी जाएगी, जिनमें मृतक अधिकारी अथवा उसके अधिकारियों का तैनाती स्थान पर अपना कोई भकान हो”।

[सं. एफ. 1/18/98/ए.एन.-II]

ए.के. पाण्डे, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 576, दिनांक 1 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तदन्तर निम्नलिखित सा.का.नि. द्वारा संशोधन किए गए :—

- (i) सा.का.नि. 279 (अ), दिनांक 17 जून, 1977
- (ii) सा.का.नि. 566 (अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 1978
- (iii) सा.का.नि. 439 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1979
- (iv) सा.का.नि. 1110 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1986
- (v) सा.का.नि. 1011 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 1987

- (vi) सा.का.नि. 3 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 1997
- (vii) सा.का.नि. 67 (अ), दिनांक 6 फरवरी, 1997
- (viii) सा.का.नि. 142 (अ), दिनांक 20 मार्च, 1998
- (ix) सा.का.नि. 247 (अ), दिनांक 6 मई, 1998

स्थायिक ज्ञापन

लोक सभा सचिवालय (आवासों का आबंटन) नियम, 1974 के नियम 8(2)(iii) और नियम 17 के उपबन्धों के अनुसार आर्बटी की मृत्यु हो जाने के मामले में लाइसेंस शुल्क का सामान्य दर से भुगतान करने पर आवास अपने अधिकार में रखने की अनुज्ञय अधिधिकार में एक वर्ष है। भारत सरकार के सामान्य पूल के आवासों के संबंध में लागू होने वाले नियमों में किये गए समान उपबन्ध के अनुलैप्त ही एक वर्ष की अधिधिकार में रखने की अनुमति दी गई थी।

भारत सरकार ने सरकारी आवासों का आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 में इस आशय के संशोधन किए गए हैं कि आर्बटी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका परिवार लाइसेंस शुल्क का सामान्य दर से भुगतान करके एक और वर्ष के लिए सरकारी आवास अपने अधिकार में रखने का पात्र होगा। इन संशोधनों को 1 जून, 1998 से लागू किया गया है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त अनुबंध 1-6-98 से लागू किया गया है, लोक सभा सचिवालय (आवासों का आबंटन) नियम में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से उसी तिथि से किया जा रहा है।

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 1998

G.S.R. 621 (E).—In exercise of the powers conferred by rule 45 of Fundamental Rules as made applicable to the officers of the Lok Sabha Secretariat by Recruitment and Conditions of Service Order No. 185, dated the 19th December, 1957, the Speaker of the Lok Sabha hereby makes the following rules further to amend the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Second Amendment Rules, 1998.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st June, 1998.

2. In the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974, in rule 17, after the proviso, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided further that in the event of death of the allottee, his/her family shall be eligible to retain the Government Accommodation for a further period of one year on payment of normal licence fee. The extended period of retention shall not be allowed in cases where the deceased officer or his/her dependents owns a house at the place of posting.”

[No. F. 1/18/98/AN-II]

A.K. PANDEY, Addl. Secy.

Footnote : The principal rules were published vide No. G.S.R. 576, dated the 1st May, 1974 and subsequently amended vide :—

- (i) G.S.R. 279(E), dated 17th June, 1977
- (ii) G.S.R. 566(E), dated 1st December, 1978
- (iii) G.S.R. 439(E), dated 7th July, 1979
- (iv) G.S.R. 1110(E), dated 26th September, 1986
- (v) G.S.R. 1011(E), dated 22nd December, 1987
- (vi) G.S.R. 3(E), dated 1st January, 1997
- (vii) G.S.R. 67(E), dated 6th February, 1997
- (viii) G.S.R. 142(E), dated 20th March, 1998
- (ix) G.S.R. 247(E), dated 6th May, 1998

EXPLANATORY MEMORANDUM

As per the provisions of Rule 8(2)(iii) and Rule 17 of the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974, permissible period of retention of accommodation is one year in case of death of the allottee on payment of normal rates of licence fee. The period of one year was prescribed in line with similar provision in rules Governing General Pool residences of Government of India.

The Government of India have since made amendments in Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules 1963 to the effect that in the event of death of the allottee, his/her family shall be eligible to retain the Government accommodation for a further period of one year on payment of normal licence fee. These amendments have been made effective from the 1st June, 1998.

In view of the fact that the above provision has been given effect by the Government of India w.e.f. 1-6-98, the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules are amended retrospectively with effect from the same date.

